



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2010/आषाढ़ 28, 1932

No. 199]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2010/ASADHA 28, 1932

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2010

अंतिम जांच परिणाम

विषय : कोरिया गणराज्य से कैथोड रे कलर पिक्चर ट्यूबों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा (नियम 22 के अंतर्गत)

सं. 15/10/2009-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटनरोधी वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली (जिसे आगे नियम कहा गया है) 1995 को ध्यान में रखते हुए;

प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- I. कोरिया गण. की मै. मैरीडियन सोलर एंड डिस्पले कंपनी लि. (एम एस डी) ने नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा करने के लिए एक आवेदन किया और निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी जांच सं. 14/8/2007-डीजीएडी में दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के शुद्धि-पत्र के साथ पठित 17 फरवरी, 2009 के अंतिम जांच परिणाम के अनुसरण में मलेशिया, थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गण. के मूल की या वहां से निर्यातित कुछेक कैथोड रे कलर पिक्चर ट्यूबों (सी पी टी) के आयातों पर 15 मई, 2009 को लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की "न्यू शिपर" समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया।
- II. आवेदकों ने यह दावा किया कि उपर्युक्त संबद्ध उत्पाद के बारे में इस समय पाटनरोधी उपायों के अधीन कोरिया गण. के निर्यातकों/उत्पादकों में से किसी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मूल जांच अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। उन्होंने उक्त जांच अवधि के पश्चात और सी पी टी कारोबार तथा एल पी डी कोरिया की संवर्धित परिसंपत्तियों का हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद निर्यात शुरू किया। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रथमदृष्टया जांच-के बाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के उपबंधों के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए इसे पर्याप्त माना।

- III. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 22 के अंतर्गत 13 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 15/10/2009-डीजीएडी के तहत कोरिया गण. की मै. मैरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कंपनी लि. (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर न्यू शिपर समीक्षा शुरू की। प्राधिकारी ने भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार शुरू की गई समीक्षा पूर्ण होने तक कोरिया गण. मै. मैरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कंपनी लि. (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा कैथोड रे कलर टेलिविजन पिक्चर ट्यूबों के सभी निर्यातों के अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की। इसे 23 दिसंबर, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 144/2009-सी.शु. के तहत अधिसूचित किया गया था।
- IV. प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगने के लिए मै. मैरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कंपनी लि. (कोरिया गण. का उत्पादक/निर्यातक) को निर्यातक प्रश्नावली की एक प्रति भेजी।
- V. इस न्यू शिपर समीक्षा में जांच की अवधि 1 जुलाई, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक की है।
- VI. प्राधिकारी ने न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरुआत के बारे में निर्यातक देश को सूचित किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच अवधि की समाप्ति अर्थात् 1 जुलाई, 09- 31 दिसंबर, 2009 से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- VII. प्राधिकारी ने 15 फरवरी, 2010 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने सुनवाई में भाग लिया था और अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे उन सभी पक्षकारों से लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपने अनुरोधों में प्रतिपक्षी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां ले लें और उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। इस प्रकार किए गए अनुरोधों को प्रकटन विवरण में ध्यान में रखा गया है।
- VIII. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों की सूचना/अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरण निहित थे।
- IX. **** यह चिन्ह इस जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद "पूर्ण या अपूर्ण कैथोड रे कलर टेलिविजन पिक्चर ट्यूब" है जिसका विस्तृत उल्लेख "थर्मियोनिक, कोल्ड कैथोड या फोटो कैथोड वाले और ट्यूबों अर्थात् वैक्यूम या

वेपर या गैस फील्डबाल्ब तथा ट्यूब, मरकरी आर्क रेक्टिफाइंग वाल्व तथा ट्यूब के रूप में किया जाता है और जिसे कैथोड रे ट्यूब, टेलिविजन कैमरा ट्यूब या कैथोड रे कलर टेलिविजन पिकचर ट्यूब या कलर टेलिविजन पिकचर ट्यूब या कलर पिकचर ट्यूब आदि के नाम से भी जाना जाता है" और इसका वर्णन इस अधिसूचना में कलर पिकचर ट्यूब या "सी पी टी" या "सी आर टी" के रूप में किया गया है। विडियो तथा कंप्यूटर मॉनीटर कैथोड रे ट्यूबें वर्तमान याचिका के दायरे में नहीं आती हैं।

4. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत उपशीर्ष सं. 8540.11 के तहत आता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल मामले में यथानिर्धारित "पूर्ण या अपूर्ण कैथोड रे कलर टेलिविजन पिकचर ट्यूब" है। किसी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने यह दावा किया है कि मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कंपनी लि. (कोरिया गण. का उत्पादक/निर्यातक) द्वारा उत्पादित और निर्यातित और एल जी इंटरनेशनल (एसपुर) पी टी ई लि., सिंगापुर (निर्यातक) द्वारा निर्यातित वस्तु नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु है। पूर्वोक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में माना गया है। अर्थात् यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकरणीय "पूर्ण या अपूर्ण कैथोड रे कलर टेलिविजन पिकचर ट्यूब" है।

हितबद्ध पक्षकारों के विचार

आवेदक अर्थात् मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कंपनी लि. (कोरिया गण. का उत्पादक/निर्यातक) के विचार: -

6. एम एस डी की स्थापना कोरिया के कानूनों के अंतर्गत संगठित और विद्यमान एम जी ए होल्डिंग कार्पो. लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 10 अप्रैल, 2009 को की गई थी। निगमन प्रमाण पत्र व्यापार लाइसेंस सं. 110111-4075936 के साथ 20 मई, 2009 को जारी किया गया था। वर्ष 2009 में मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले की संस्था के अंतर्नियम प्रभावित हुए और वे संगठन के विनियमन तथा कंपनी और शेयरधारकों के मध्य तथा शेयरधारकों के बीच संबंध को लागू करने के लिए बाध्यकारी दस्तावेज बने। जहां तक एम एस डी/प्रवर्तक का संबंध है, इसकी कोई संबद्ध कंपनी नहीं है और एम एस डी ऐसे किसी निर्यातक/उत्पादक से संबद्ध नहीं है जिन पर कोरिया में सी पी टी पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।

7. एम एस डी ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत को सी पी टी का कभी निर्यात नहीं किया है। एम एस डी ने उक्त जांच अवधि के बाद और वस्तुतः जुलाई, 2009 में एल पी डी, कोरिया के सी पी टी व्यापार तथा संबद्ध परिसंपत्तियों को हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद भारत को सी पी टी का निर्यात शुरू किया।

8. एल पी डी कोरिया एक विशिष्ट विधिक कंपनी बनी रही और उसने सी पी टी का व्यापार नहीं किया। अतः एम एस डी एक न्यू शिपर है।
9. एम एस डी ने यह प्रस्ताव किया था कि एन एस आर जांच अवधि 24 जुलाई, 2009 से 31 जुलाई, 2010 की होनी चाहिए अथवा इसका निर्णय माननीय प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। माननीय प्राधिकारी ने इस एन एस आर हेतु जांच अवधि 1 जुलाई, 2009 से 31 जुलाई, 2010 तक की चुनी। एम एस डी ने कभी यह दावा नहीं किया कि 24 जुलाई, 2009 से पूर्व हुए किसी निर्यात के आधार पर पाटन मार्जिन का पुनः निर्धारण किया जाए। एम एस डी को एन एस आर जांच अवधि में 1-23 जुलाई, 2009 की अवधि पर विचार न करने के बारे में माननीय प्राधिकारी के प्रति कोई आपत्ति नहीं है।
10. एम एस डी द्वारा किसी व्यापारी के जरिए न तो एन एस आर की तारीख को और न ही एन एस आर की शुरुआत की तारीख को भारत को कोई निर्यात किया गया है। अतः एम एस डी ने कोई बात नहीं छुपाई है परंतु चूंकि मूल जांच में अत्यंत सावधानी की वजह से और किसी असंबद्ध व्यापारी द्वारा तथ्यों को छुपाने या सहयोग न करने के किसी आरोप से बचने के लिए किसी भी संबद्ध देश के मूल की सी पी टी शामिल थी। इसलिए एन एस आर जांच अवधि की समाप्ति पर एकमात्र असंबद्ध व्यापारी द्वारा भारत को किए गए निर्यात की सूचना एम एस डी ने दी थी और असंबद्ध व्यापारी (अर्थात् एल जी इंटरनेशनल (एसपुर) पी टी ई लि., सिंगापुर) से यह अनुरोध किया गया था कि वह समर्थकारी व्यापारिक उत्तर दायर करें जो उसने किया भी था। भारत को हुए अन्य सभी निर्यात एम एस डी ने सीधे किए थे। अतः एम एस डी अपने खुद के उत्तर के आधार पर एन एस आर पाटन मार्जिन का पुनः निर्धारण प्राप्त कर सकता है। एम एस डी द्वारा किए गए सभी निर्यात एन एस आर की शुरुआत की तारीख तक अन्य दरों तक किए गए थे और वे उसके बाद बाध्य थीं।
11. एम एस डी की एल पी डी- के, एल पी डी, एल जी, एल जी ई, एल जी आई आदि के निदेशकों अथवा इन कंपनियों में अथवा एल पी डी के न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों के साथ कोई शेयरधारिता नहीं है। यह ऐसी किसी तीसरी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में भी नहीं है जिसके पास एल पी डी- के, एल पी डी, एल जी, एल जी ई, एल जी आई का स्वामित्व या नियंत्रण है। स्पष्ट तौर पर व्यापार में नए प्रवेशकर्ता के रूप में एम एस डी का विपणन गुणवत्तायुक्त सी पी डी के उत्पादन में अपेक्षित परिसंपत्तियों के सुस्थापित अनुभव पर निर्भर करेगा।
12. सी ओ ओ एम एस डी के निदेशक मंडल में नहीं हैं और न ही सी ओ ओ एल पी डी - के/एल पी डी में तुलनीय वरिष्ठता में रही है। निदेशक स्तर से कम के सभी कार्यकारियों के लिए उस समय परिवर्तन करना सामान्य नहीं होता है जब ऐसी कोई बिक्री होती है। केवल एक कार्यकारी उक्त स्तर पर बना रहा जिसे "नियंत्रण" में समग्र परिवर्तन का पता चलता है।
13. घरेलू उद्योग ने न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती दी है। उनकी शिकायत का आधार पूर्णतः गलत और अविचारित है। आवेदक उत्पादक/निर्यातक कानून द्वारा सृजित एक विधिक कंपनी है न कि कोई प्रकृत व्यक्ति। कानून द्वारा सृजित कोई कंपनी तब अस्तित्व में आती है जब वह अपना पंजीकरण प्राप्त कर लेती है अथवा दूसरे शब्दों में जब वह निगमित हो जाती है।

निगमन या पंजीकरण प्रमाणपत्र में एम एस डी जैसी विधिक कंपनी के अस्तित्व में आने की तारीख के बारे में अंतिम साक्ष्य प्रदर्शित होता है। हमने यह साक्ष्य देते हुए प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है कि यह कंपनी केवल 2009 में अस्तित्व में आई है। अतः इस बात की पुष्टि की जाती है कि मूल जांच अवधि के दौरान यह न तो अस्तित्व में थी और न ही इसने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया। इस उत्पाद का नया कारोबार शुरू करने के कारण यह निश्चित तौर पर एक नया निर्यातक है और भारतीय पाटनरोधी कानून के प्रावधान के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पृथक पाटन मार्जिन का पात्र है। एल पी डी-के कोरिया में पृथक असंबद्ध विधिक कंपनी बनी हुई है।

14. घरेलू उद्योग के परामर्शदाताओं द्वारा किए गए अनुरोधों से यह पता चलता है कि वे नई कंपनी के नाम में परिवर्तन तथा उसके अस्तित्व में आने के बारे में भ्रमित हैं। नाम में परिवर्तन होने की स्थिति में उक्त कंपनी पुरानी पंजीकरण संख्या और तारीख के साथ प्रचालन जारी रखती है परंतु ऐसे अनुमोदन की तारीख से नाम में परिवर्तन हेतु पंजीकरण प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करती है। पंजीकरण के बारे में कोई नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। प्राधिकारी के समक्ष यह पूर्णतः स्पष्ट किया गया था कि हमारी कंपनी संबद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक नई कंपनी है। इस बात की कहीं भी परिकल्पना नहीं की गई है कि किसी नई कंपनी के लिए अपनी खुद की नई उत्पादन सुविधा स्थापित करनी अपेक्षित होती है। लगभग सभी देशों में आधुनिक सरकारों द्वारा यह विधिवत प्राधिकृत किया गया है कि किसी नई कंपनी या सत्ता द्वारा कोई मौजूदा संयंत्र अर्जित किया जा सकता है और उसमें तुरंत उत्पादन शुरू किया जा सकता है। भारत में भी कई भारतीय उत्पादन सुविधाएं नई कंपनियों के लिए अपेक्षित हो रही हैं। किसी मौजूदा इकाई की उत्पादन सुविधा हासिल करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उक्त नई कंपनी उसके निगमन की तारीख से पूर्व संबद्ध उत्पाद हेतु मौजूद होनी चाहिए और उसका उत्पादन करना चाहिए। हमारी कंपनी केवल वर्ष 2009 में निगमित हुई थी और इसलिए मूल जांच में उत्पादन या निर्यात का प्रश्न नहीं उठता है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग "उत्पादक" शब्द के बारे में भ्रमित है। उनके स्वयं भ्रमित होने के कारण उन्होंने "उत्पादन सुविधाओं" के साथ "उत्पादक" को बराबर लाकर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश की है। उत्पादक वह होता है जो उत्पादन सुविधाओं के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना उत्पादन करता है। किसी उत्पादक के पास कोई उत्पादन सुविधा नहीं हो सकती है परंतु वह अन्य फैक्ट्री में "उजरती कार्य" के आधार पर या किराए पर अपना उत्पादन करवा सकता है। इस प्रकार स्वामित्व "उत्पादन" या "उत्पादक" से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। उत्पादक प्रकृत व्यक्ति या विधिक कंपनी के रूप में ऐसी सत्ता होती है जो उत्पादन सुविधा के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना उत्पादन करती है। किसी उत्पादक के लिए किसी संयंत्र/फैक्ट्री का स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है। एम एस डी ने मौजूदा संयंत्र की खरीद की और उसके निगमन के बाद संबद्ध वस्तु का उत्पादन कराया। अतः एम एस डी 22 जुलाई, 2009 के बाद ही संबद्ध वस्तु की उत्पादक बनी न कि उसके पूर्व। अतः उसके नए उत्पादक की हैसियत के बारे में कोई शंका नहीं है।

16. घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों से लिए गए निम्नलिखित उद्धरणों से भी उनके भ्रम

"किसी उत्पादक के लिए निम्नलिखित बातें सामूहिक रूप से प्रासंगिक हैं-

- (क) स्वामित्व - उस सीमा तक जिस सीमा तक भी पूंजी जुटाते हैं और परसंपत्तियों का स्वामित्व रखते हैं तथा देनदारियां मानते हैं ।
- (ख) कंपनी ऐसे कई व्यक्तियों के प्रबंधन में होती है जिन्हें प्रबंधन माना जाता है ।
- (ग) जनशक्ति - कोई कंपनी ऐसे कई लोगों द्वारा संचालित होती है जिनमें कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल लोग शामिल होते हैं ।
- (घ) मशीनें - कोई कंपनी विशेष रूप से लगाई गई और प्रयोग में लाई गई ऐसी मशीनों के उपयोग से उत्पाद के उत्पादन का उत्पादन करती है ।
- (ङ) सामग्री - कोई कंपनी उत्पाद के उत्पादन हेतु निर्धारित सामग्री का उपयोग करती है ।
- (च) धन-किसी कंपनी को अपना प्रचालन करने के लिए धन की जरूरत होती है ।"

घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त तथ्यों को एक साथ लाने पर कोई कंपनी तब गठित होती है जब वह उत्पादन करती है और बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री करती है ।

17. पाटन मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में उपर्युक्त तथ्यों की प्रासंगिकता को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:-

- (क) कंपनी का प्रबंधन विचाराधीन उत्पाद के दैनिक उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेवार होता है । प्रबंधन द्वारा ही ऐसी मात्रा और कीमत के बारे में निर्णय लिया जाता है जिसकी किसी बाजार विशेष में बिक्री करनी होती है । कंपनी के प्रबंधन द्वारा ही किस कीमत पर और कितनी मात्रा में कहां पर उत्पाद की बिक्री करने के बारे में निर्णय लिया जाता है । हालांकि यह सच है कि प्रबंधन बोर्ड से निर्देश या आदेश प्राप्त करता है-तथापि, यह स्वीकार किया जा सकता है कि उत्पाद की दैनिक बिक्री और उसकी कीमत सामान्यतः प्रबंधन द्वारा शासित होती है ।
- (ख) सामान्य मूल्य उत्पादन लागत से अत्यंत संबद्ध होता है । उत्पादन की ऐसी लागत सामग्री की लागत, श्रम लागत, प्रसंस्करण/विनिर्माण लागत, मूल्य ह्रास तथा अन्य लागत की राशि होती है ।

18. उपर्युक्त से घरेलू उद्योग यह महसूस करता है कि जब स्वामित्व, प्रबंधन, जनशक्ति, मशीनों, सामग्री और धन को एक साथ लाया जाता है तो ऐसी कंपनी गठित होती है जो उस वस्तु का उत्पादन कर उसकी बाजार में बिक्री करती है । ये पुनः भ्रमित हैं । स्वामित्व का तात्पर्य ऐसे उत्पादक से नहीं है जिसे उत्पादन सुविधाओं का स्वामी होना जरूरी है । अन्य की उत्पादन सुविधाओं के साथ कोई उत्पादक दूसरे की जनशक्ति का उपयोग कर सकता है । यदि डी एस एम उजरती कार्य के प्रभार के आधार पर अल्का रिमैडिज फेक्ट्री में 6 एपीए एंटीइन्फेक्टिव का उत्पादन करती है तो डी एस एम एंटी-इन्फेक्टिव का उत्पादक है ।

19. पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में उपर्युक्त कारकों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करते समय उन्हें पुनः भ्रम हुआ है । स्वामित्व नहीं अपितु प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण होता है । न तो उत्पादन सुविधा और न ही स्वामित्व का उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, बिक्री मात्रा पर प्रभाव पड़ता है कुशल प्रबंधन वह

होता है जो घाटा उठाने वाली कंपनी को लाभ कमाने वाली कंपनी में बदल देता है। आई पी सी एल की लागत, कीमत और लाभप्रदता में तब परिवर्तन आया जब प्रबंधन आर आई एल में चला गया। उसी विनिर्माण सुविधा का अकुशल से एक कुशल प्रबंधन में परिवर्तित होने का अलग परिणाम मिलता है। घरेलू उद्योग ने यह माना है कि उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सब कुछ वही रहेगी जैसी कि हमारी कंपनी की उत्पादन सुविधा किसी मौजूदा कंपनी ने अपने हाथ में ले ली है। प्रबंधन द्वारा ऐसे सभी परिवर्तन किए जाते हैं जो आर आई एल द्वारा आई पी सी एल को अपने अधिकार में लेने के बाद किए गए हैं। एम एस डी का अपना खुद का प्रबंधन है और उसका अपना दृष्टिकोण तथा लागत एवं विपणन कार्यनीति है। एम एस डी का अपना खुद का उत्पादन, खुद की लागत और खुद की विपणन नीति है। एम एस डी ने प्राधिकारी को अपनी लागत, घरेलू बिक्री कीमत, निर्यात कीमत का सत्यापन करने की पेशकश की है। यदि माननीय प्राधिकारी कोई पाटन पाते हैं तो वे पृथक पाटन निर्धारित कर सकते हैं और तदनुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं। प्राधिकारी नए उत्पादक के रूप में एम एस डी पर विचार करने और दायर किए गए अनुरोध तथा दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद नियमानुसार जांच करने के लिए पूर्णतः सही हैं। घरेलू उद्योग की आपत्ति केवल गलत अवधारणा पर आधारित है।

20. एम एस डी संगत सूचना के साथ जांच में प्राधिकारी का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह संकेत देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा है कि एल पी डी - के और एम एस डी के शेयरधारक समान हैं अथवा संबंधित निदेशक मंडल में कोई निदेशक समान हैं अथवा एम एस डी तथा एल पी डी - के का स्वामित्व किसी साझा कंपनी के पास है। कोई सामान्य शेयरधारिता, निदेशक या सामान्य नियंत्रण या कोई संबद्धता नहीं है।

21. स्वामित्व और प्रबंधन ही पाटन के लिए जिम्मेवार होता है न कि संयंत्र या मशीनरी। अन्यथा अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं होता तथा डी जी ए डी सहित विभिन्न प्राधिकारी समग्र क्षेत्राधिकार में कई जांचों में एक ही देश से कई बार समान संयंत्र और मशीनरी रखने वाली अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का आकलन नहीं करते। अतः घरेलू उद्योग के अनुरोध पाटनरोधी जांचों के आधार और तर्क के प्रतिकूल हैं।

22. मलेशिया से संबंधित एफ डी वाई एम टी आर के तथ्य प्रथम दृष्टया अलग हैं क्योंकि जांच परिणाम में यह कहीं दर्ज नहीं किया गया है कि हुआलोन तथा रेक्रोन के बीच कोई सामान्य निदेशक हैं अथवा हुआलोन मलेशिया विधिक कंपनी अर्जन से बच गई (यद्यपि परिसंपत्ति के बिना) तथा यह भी कि संबंधित मूल जांच की अवधि के दौरान नए स्वामी, रिलायंस ग्रुप स्पष्टतः विद्यमान थे और वे संबद्ध मूल जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु के स्पष्टतः उत्पादक थे। एम एस डी के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य पूर्णतः अलग हैं।

23. एम एस डी को एक उत्पादक निर्यातक के रूप में उसे स्वयं या एल जी आई के साथ इस एन एस आर में अलग-अलग निर्धारण का लाभ मिल सकता है। एम एस डी 22 जुलाई, 2009 से शुरू होने वाली जांच अवधि का विरोध नहीं करती है। एम एस डी का माननीय प्राधिकारी से अनुरोध है कि "सुविधा संतुलन" के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए। इसका विकल्प माननीय प्राधिकारी के

लिए सुविधाजनक होगा अर्थात् एन एस आर हेतु एम एस डी के अनुरोध के आधार पर तुरंत एम जी आर शुरू करना (उसे एम टी आर का अनुरोध मानते हुए) ।

24. इसके अलावा, माननीय प्राधिकारी को उसकी सुस्थापित पद्धतियों और भारतीय प्रावधानों का ज्ञान होगा । घरेलू उद्योग ने ई यू/ई सी की पद्धति के साक्ष्य से संगत उद्धरण या उसका उल्लेख एन सी वी डब्ल्यू एस में नहीं किया कि उन्होंने इस पर भरोसा किया है । यद्यपि, यह प्रकाशित सामग्री होगी और इस अवधारणा के उल्लंघन द्वारा गोपनीयता का भंग नहीं माना जा सकता । प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए उपर्युक्त एफ डी वाई एम टी आर मामले में देखा जा सकता है कि प्रत्येक मामले के संगत तथ्य का स्वयं सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए ।

एल जी इंटरनेशनल (सिंगापुर) पीटीई लि., सिंगापुर (व्यापारी/निर्यातक)

25. एल जी आई एम एस डी, एल जी ई, एल पी डी कोरिया से संबंधित नहीं है अथवा नीदरलैंड न्यायालय ने एल पी डी के प्रशासक नियुक्त किए हैं । शेयरधारक और निदेशक अलग-अलग हैं और एल जी आई पर स्वामित्व या नियंत्रण किसी साझा कंपनी का नहीं है ।

26. एल जी आई किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है जिन पर कोरिया में सी पी टी पर पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

27. एल जी आई द्वारा किसी व्यापारी के जरिए न तो एन एस आर की तारीख को और न ही एन एस आर की शुरुआत की तारीख को भारत को कोई निर्यात किया गया है । अतः एल जी आई ने कोई बात नहीं छुपाई है परंतु चूंकि मूल जांच में अत्यंत सावधानी की वजह से और किसी असंबद्ध व्यापारी द्वारा तथ्यों को छुपाने या एल जी आई के किसी असंबद्ध व्यापारी द्वारा समर्थकारी व्यापार उत्तर दायर करने के एम एस डी के अनुरोध पर असहयोग करने के किसी आरोप से बचने के लिए किसी भी संबद्ध देश के मूल की सी पी टी शामिल थी । इसलिए एल जी आई एम एस डी उत्पादों के लिए अपने उत्तर के आधार पर एन एस आर पाटन मार्जिन का पुनःनिर्धारण प्राप्त कर सकता है । घरेलू उद्योग ने सुनवाई में यह स्वीकार किया है कि एक ही सौदा पर्याप्त होता है ।

28. माननीय प्राधिकारी नियम 22 और पाटनरोधी अधिनियम द्वारा बाध्य हैं । नियमों में "नियंत्रण" पर जोर दिया गया है जिसके लिए स्वामित्व की जांच की जाती है । एल जी आई की एम एस डी, एल पी डी-के, एल पी डी, एल जी, एल जी ई आदि के निदेशकों अथवा इन कंपनियों में अथवा एल पी डी के न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों के साथ कोई शेयरधारिता नहीं है । एल जी आई ऐसी किसी तीसरी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में भी नहीं है जिसके पास एम एस डी, एल पी डी-के, एल पी डी, एल जी, एल जी ई, का स्वामित्व या नियंत्रण है । एल जी आई न तो अब और न ही जांच अवधि के दौरान एम एस डी, एम जी जी, एल पी डी-के से संबद्ध रही है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि एल जी ई, एल पी डी-के तथा एल जी आई के शेयरधारक सामान्य हैं और संबंधित निदेशक मंडल में कोई सामान्य निदेशक है अथवा एल जी आई तथा एल पी डी-के का स्वामित्व साझा कंपनी के पास है । ऐसी कोई साझा शेयरधारिका, निदेशक या साझा नियंत्रण या कोई संबद्धता नहीं है ।

29. एल जी आई के लिए कोई शुद्धि पत्र अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार यह समीक्षा उचित है । एल जी आई कुछ राहत की पात्र है चूंकि एल जी आई ये नहीं मानती है कि वह कोई संबद्ध पक्षकार है । अपितु, वह यह मानती है कि वह इस एन एस आर में भाग लेने की पात्र है ।

30. मूल एल पी डी नियंत्रक कंपनी ऐसी कुछेक एल जी तथा फिलिप्स समूह की कंपनियों के 50:50 के स्वामित्व वाला सी पी टी विशिष्ट संयुक्त उद्यम थी, जो स्वयं एल जी तथा फिलिप्स समूह को कंपनी कानून तथा प्रतिस्पर्धा कानून में अधिकांश क्षेत्राधिकारों के भीतर समान संबंध के उपबंधों के अंतर्गत सभी उत्पादों के एक संयोजन के रूप में उनके बचाव हेतु संबंधित समूह के भीतर स्वयं विशेष साधन थे ।

31. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें एल जी समूह की कंपनी के पास 50% स्वामित्व होगा और शेष दूसरों के पास होगा । यहां फिलिप्स समूह की कंपनी का स्वामित्व शेष 50% का है अतः इस मामले में शेयरधारिता के आधार पर न तो एल जी और न ही फिलिप्स समूह के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके पास एल पी डी समूह का नियंत्रण है । इसके अलावा, वर्ष 2006 के पूर्वार्ध से से नीदरलैंड न्यायालय ने किसी भी मामले में एल पी डी के प्रबंधन के नियंत्रण हेतु स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त नहीं किए हैं । अतः न तो एल जी और न ही फिलिप्स समूह किसी भी कानून में मूल जांच अवधि अथवा उसके बाद एल पी डी समूह की कंपनियों के प्रबंधन में किसी भी रूप में शामिल नहीं हैं । एल जी आई ने भी 1 जुलाई, 2009 के बजाए 22 या 24 जुलाई, 2009 से शुरू होने वाली एन एस आर जांच अवधि पर कोई आपत्ति नहीं की है । इन सभी कारणों से एल जी आई यह मानती है कि वह पात्र न्यू शिपर है और वर्तमान एन एस आर में भाग लेने तथा अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की पात्र है ।

32. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि एक ही सौदा पर्याप्त है इसलिए एल जी आई समीक्षा की पात्र होगी । एम टी आर के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसी सौदे के लिए फाइल पुनः खोलने, एम टी आर शुरू करने, संसाधन जुटाने तथा कोरिया एवं सिंगापुर और ऐसे ही देशों में उसी प्रकार का सत्यापन करने के लिए बाध्य होंगे । इस प्रकार "सुविधा संतुलन" की दृष्टि से भी एल जी आई को उक्त एन एस आर में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है ।

33. यदि माननीय प्राधिकारी भिन्न मत अपनाते हैं तो एल जी आई के उत्तर को एम टी आर का आवेदन माना जाए क्योंकि अनंतिम शुल्क के बाद एक वर्ष बीत गया है और माननीय प्राधिकारी एम टी आर शुरू कर सकते हैं ।

34. स्वामित्व एवं प्रबंधन ही पाटन के लिए जिम्मेवार होते हैं न कि संयंत्र या मशीनरी । अन्यथा अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं होगा और डी जी ए डी सहित विभिन्न प्राधिकारियों ने समस्त क्षेत्राधिकारों में की गई इतनी जांचों में उसी देश से कई बार समान संयंत्र एवं मशीनरी रखने वाली अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग पाटन मार्जिन नहीं पाया होगा । इस प्रकार घरेलू उद्योग के अनुरोध पाटनरोधी जांच के आधार और तर्कशास्त्र के प्रतिकूल हैं ।

35. मलेशिया के बारे में एफ डी आई एम टी आर के तथ्य अलग हैं क्योंकि जांच परिणाम में यह बात कहीं दर्ज नहीं की गई है कि हुआलोन तथा रेक्रोन के बीच कोई सामान्य निदेशक है अथवा यह कि हुआलोन, मलेशिया विधिक कंपनी अधिग्रहण (यद्यपि उसकी परिसंपत्ति के बिना) से बच गई है और यह भी कि नए मालिक, रिलायंस ग्रुप मूल जांच अवधि के दौरान जाहिर तौर पर मौजूद थे तथा संबंधित मूल जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु के जाहिर तौर पर उत्पादक थे। एल जी आई के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य पूर्णतः अलग हैं।

36. एक समर्थक व्यापारी के रूप में एल जी आई को एम एस डी के साथ इस एन एस आर में अलग निर्धारण का लाभ मिल सकता है। माननीय प्राधिकारी को स्वयं तथा एल जी आई और एम एस डी, दोनों के लिए "सुविधा संतुलन" को भी ध्यान में रखना है। एल जी आई ने भी जांच अवधि 22 जुलाई, 2009 से शुरू होने का प्रस्ताव नहीं किया है। विकल्पतः माननीय प्राधिकारी एल जी आई के समर्थनकारी उत्तर को एम टी आर का अनुरोध मान सकते हैं।

37. इसके अलावा, माननीय प्राधिकारी को उसके सुस्थापित व्यवहारों और भारतीय उपबंधों का ज्ञान होगा। घरेलू उद्योग ने एन सी वी डब्ल्यू एस में ई यू/ईसी की पद्धति से इस आशय के संगत उद्धरण अथवा उसके साक्ष्य को संलग्न नहीं किया कि उन्होंने उन पर भरोसा किया है यद्यपि, यह प्रकाशित सामग्री होगी जिसकी वजह से कल्पनातीत रूप में वह गोपनीय नहीं मानी जा सकती। एल जी आई के पास ये ब्यौरे प्रकटित होने के बाद आगे टिप्पणी करने का अधिकार सुरक्षित है। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसेमंद उपर्युक्त एफ डी आई एम टी आर से यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक मामले के संगत तथ्यों का खुद सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग के एक घटक सेमटैल कलर लि. के विचार

38. वर्तमान मामले में उल्लिखित परिस्थितियां नियम 22 के अंतर्गत वर्तमान मामले में विचार करने के लिए अपर्याप्त हैं।

39. कंपनी का प्रबंधन विचाराधीन उत्पाद के दैनिक उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेवार है।

40. सामान्य मूल्य उत्पादन लागत से अत्यंत संगठित होता है। उत्पादन की ऐसी लागत सामग्री, श्रम लागत, प्रसंस्करण/विनिर्माण लागत, मूल्यहास और अन्य लागतों की एक राशि होती है।

41. वर्तमान मामले में स्पष्टतः केवल जांच अवधि के बाद स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं बनता है कि स्वामित्व में परिवर्तन होने से, प्रबंधन, जनशक्ति, मशीनों तथा सामग्री में परिवर्तन हो गया है। आवेदक ने यह दावा ही नहीं किया है कि सामान्य मूल्य के लिए जिम्मेवार किसी कारक में स्वामित्व के परिणामस्वरूप परिवर्तन आया है।

42. नाम में परिवर्तन के संबंध में सामान्य परंपरा यह है कि नाम में परिवर्तन का कोई अनुरोध तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि नाम में परिवर्तन होने से पाटनरोधी शुल्क लगाने को विनियमित करने वाले जांच परिणाम पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

43. आवेदक का यह दायित्व है कि वह यह प्रदर्शित करे कि क्या उसके मामले से संबंधित तथ्य केवल नाम में परिवर्तन से संबंधित है अथवा नाम में परिवर्तन उस सामान्य मूल्य से संबंधित मापदंडों के बारे में इतना महत्वपूर्ण है कि पाटन मार्जिन मूलतः पूर्व में निर्धारित पाटन मार्जिन से भिन्न हो गया है।

44. चूंकि प्रथमदृष्टया जनशक्ति, मशीनों, बाजार तथा सामग्री समस्त संपत्तियों सहित पूर्ण स्वामित्व का अंतरण मै. एल जी फिलिप्स डिस्पेज कोरिया कं. लि. से मै. मैरीडियन सोलर डिस्पेज कंपनी लि. को कर दिया गया है। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें आवेदक को नया उत्पादक मानना न्यायोचित ठहराया जा सके। कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन मात्र का तात्पर्य यह नहीं है कि कंपनी की संरचना और पहचान में ऐसा मूलभूत परिवर्तन आया है जिससे आवेदक को नया उत्पादक माना जा सके। पुरानी कंपनी की सभी परिसंपत्ति तथा देनदारियां नई कंपनी को अंतरित कर दी गई हैं। आवेदक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए नियम 22 के अंतर्गत विधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। मै. मैरीडियन सोलर डिस्पेज कंपनी लि. की संरचना और मै. एल जी फिलिप्स डिस्पेज कोरिया कं. लि. के साथ उसके संबंध के बारे में साक्ष्य सुनवाई के समय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है।

45. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा "इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया तथा चीनी ताईपेई के मूल के या वहां से निर्यातित ऑल फुली ड्रॉन अथवा फुली ओरिएन्टेड यार्न/स्पन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न" के मामले में लगभग इन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न स्थितियों के लिए अन्य जांच की जा रही है।

46. निर्विवाद रूप से संयंत्र मूल जांच के समय दिवालियापन न्यास के नियंत्रण में था। एल पी डी ने मूल जांच के समय उसकी विधिक स्थिति तथा स्वामित्व के बारे में कुछ दावे किए हैं। स्वामित्व/नियंत्रण निर्विवाद रूप से उसी कंपनी के बाद बना रहा जिसके पास 1-23 जुलाई, 2009 की अवधि के दौरान स्वामित्व/नियंत्रण था। जाहिर है कि इसी अवधि में निर्यात हुए हैं। ऐसा मामला होने के कारण यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि मूल जांच अवधि तथा वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसी संयंत्र से निर्यात नहीं हुए थे।

47. वर्तमान मामले में जांच अवधि 1 जुलाई, 2009 से शुरू हुई है। स्पष्टतः वर्तमान कंपनी 22 जुलाई, 2009 से निगमित हुई थी। 1 से 21 जुलाई, 2009 के बीच कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण उसी कंपनी के पास था जो मूल जांच अवधि के दौरान उस पर नियंत्रण रख रही थी। इस प्रकार जाहिर तौर पर आवेदक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मूल जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है।

48. आवेदक उत्पादक द्वारा (क) प्रत्यक्ष, तथा (ख) एल जी इंटरनेशनल के जरिए प्रयोग किए गए बिक्री के दो माध्यमों का उपयोग किया है। एल जी इंटरनेशनल उस उत्पादक से पहले से ही संबद्ध है जिसकी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की थी।

49. मूल जांच के समय उत्पादक एल जी कोरिया एंड फिलिप्स के स्वामित्व वाली कंपनी एल जी फिलिप्स था ।

50. वर्तमान अवधि में भारत को निर्यात एल जी इंटरनेशनल ने किए हैं । निर्विवाद रूप से एल जी इंटरनेशनल, एल जी कोरिया से संबद्ध है ।

51. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उत्पादक-निर्यातक का संयोजन मूल जांच में उत्पादक-निर्यातक के संयोजन से संबद्ध है । इस वजह से भी न्यू शिपर समीक्षा से संबंधित शर्तों की पूर्ति नहीं हो सकती है ।

52. नियम 22 में उत्पादक तथा निर्यातक दोनों का उल्लेख है । उक्त नियम उत्पादक तक ही सीमित नहीं है । इसके अलावा, इसमें उत्पादक के "संबद्ध निर्यातक" का उल्लेख नहीं है । अतः यह नितांत अप्रासंगिक है कि निर्यातक उत्पादक से संबद्ध नहीं है । उत्पादक तथा निर्यातक शब्द को एक दूसरे के स्थान पर देखा जा सकता है जब दोनों का प्रावधान नियमों में विशेष रूप से किया गया हो ।

53. आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि मूल जांच अवधि के दौरान उसने कोई निर्यात नहीं किया था । आवेदक ने यह भी सिद्ध नहीं किया है कि मूल जांच अवधि के दौरान वह किसी निर्यातक/उत्पादक से संबद्ध नहीं था । इसके अलावा, वर्तमान अवधि में निर्यातकों में से एक निर्यातक स्पष्टतः पूर्ववर्ती जांच अवधि में एक निर्यातक से संबद्ध था । इन सभी वजहों से नियम 22 के अंतर्गत पृथक पाटन मार्जिन स्पष्टतः अनुचित है ।

54. स्वामित्व को छोड़कर पूर्ववर्ती जांच अवधि तथा वर्तमान जांच अवधि के बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

55. अपने अनुरोधों के निष्कर्ष के रूप में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार उल्लेख किया है:

- i. घरेलू उद्योग और आवेदक दोनों ही नाम में परिवर्तन पर सहमत हैं ।
- ii. विधिक स्थिति में परिवर्तन का तात्पर्य "नई कंपनी" से नहीं है ।
- iii. न्यू शिपर समीक्षा का प्रावधान उन उत्पादकों की चिंताओं के समाधान के लिए किया गया है जिन्होंने या तो उक्त अवधि में निर्यात नहीं किया था अथवा जिसने बाद में उत्पादन शुरू किया था ।
- iv. केवल स्वामित्व "उत्पादक" का बैरोमीटर नहीं हो सकता । उत्पादक एक अत्यंत व्यापक शब्द है और इसमें स्वामित्व, प्रबंधन, जनशक्ति, मशीनें, धन और सामग्रियां शामिल होती हैं ।
- v. स्वामित्व को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । ऐसा कोई कारक नहीं है जिसकी वजह से इस स्वामित्व के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत या पाटन मार्जिन

में परिवर्तन हो सकता हो । इसके अलावा, पाटन मार्जिन में परिवर्तन होने पर भी यह मध्यावधिक समीक्षा का मामला बनता है ।

- vi. यदि पाटन मार्जिन की समीक्षा करनी होती है तो घरेलू उद्योग विशिष्ट शुल्क लगाने का अनुरोध करता है ।
- vii. आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाए;
- viii. शुरु की गई कार्यवाही समाप्त की जाए क्योंकि आवेदन में नियम 22 के अंतर्गत विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है;
- ix. तथापि, घरेलू उद्योग को आवेदक को पाटनरोधी शुल्क का उसी स्तर प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की गई कंपनी एल जी फिलिप्स को प्रदान किया गया था ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

56. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा शुरु की थी जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

"नियम 22 : (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी ।"

57. नियम 22 में ऐसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनमें अलग पाटन मार्जिन की गणना हेतु न्यू शिपर समीक्षा की जा सकती है । संदर्भाधीन निर्यातक देश के किसी निर्यातक या उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

- क. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है; और,
 ख. कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाता है कि वे निर्यातक देश में किसी निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध नहीं हैं जिसकी संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

58. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि नियम 22 की भावना ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की है जिसने मूल जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया था । चूंकि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों ने मूल जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी मूल जांच के समय पाटन का निर्धारण नहीं कर सकते । अतः न्यू शिपर समीक्षा के प्रावधान का उद्देश्य इस बात पर विचार करते हुए इन निर्यातकों को मूल जांच के दौरान अवशिष्ट पाटन मार्जिन प्रदान किया गया है, अपने खुद के पाटन मार्जिन का दावा करने के लिए ऐसे किसी निर्यातक को अवसर प्रदान करना है ।

59. वर्तमान मामले में मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि. (कोरिया गण. का उत्पादक/निर्यातक) ने न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन किया है । जांच की शुरुआत के बाद और जांच अवधि के पश्चात कोरिया गण. में संबद्ध उत्पादक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का दावा करते हुए (मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि., कोरिया के अलावा) एल जी इंटरनेशनल (सिंगापुर) पी टी ई. लि., सिंगापुर (निर्यातक) ने भी उत्तर दायर किया था ।

60. अपने आवेदन में आवेदकों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दावे किए थे :-

- क. कि आवेदक ने मूल जांच अवधि के दौरान सामग्री का निर्यात नहीं किया था;
 ख. कि आवेदक ऐसी किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है जिसने मूल जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था ।

61. प्राधिकारी ने मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि. (कोरिया गण. का उत्पादक/निर्यातक) तथा एल जी इंटरनेशनल (सिंगापुर) पी टी ई. लि., सिंगापुर (निर्यातक) द्वारा प्रश्नावली के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों का मौके पर सत्यापन किया । गुमी स्थित फैक्टरी परिसर के दौरे के समय कोरिया गण. के उत्पादक के रिकॉर्डों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि फैक्टरी में प्रदर्शित किया गया नाम एल जी डिस्प्लेज था जो नाम एन एस आर तथा परिणामी अलग क्षति मार्जिन कीमांग करने वाली नव-स्थापित मेरिडियन सोलर डिस्प्लेज द्वारा परिसंपत्तियां तथा देनदारियां अर्जित किए जाने सू पूर्व था । भाण्डागार के दौरे से भी यह पता चला कि उन्होंने पूर्ववर्ती एल पी डिस्प्लेज का ही लोगो जारी रखा और विनिर्मित सी आर टी/सी पी टी का विपणन भी विनिर्मित तथा विभिन्न गंतव्यों को पोतलदान के लिए तैयार उत्पाद पर लगाए गए लेबलों के अनुसार एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज के नाम से किया गया था । पूर्ववर्ती एल पी डिस्प्लेज के लोगो आदि बनाए रखने के तर्क के बारे में जारी सत्यापन रिपोर्ट के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

क) जैसा कि दायर किए गए बी ए टी ए (व्यापार एवं परिसंपत्ति हस्तंतरिकरण करार) से स्पष्ट होता था, हांगकांग में पंजीकृत एम जी ए होल्डिंग कॉर्पो. लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली मेरिडियन

सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि. ("एम एस डी") को एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज कोरिया लि. (एल पी डी के) को की गई बिक्रियां 3 अम्ब्रैला सौदों के चरण 1 की थीं जिनमें से चरण 2 और 3 में इंडोनेशिया तथा बीजिंग की इकाइयों का अर्जन शामिल है जिसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि सौदा पूरा करने के लिए कई मर्दे बकाया हैं। बाद में पूर्ववर्ती एल पी डी के ब्राजील में हो रहे प्रचालनों के भाग का भी संभावित अर्जन किया जा सकता है लेकिन इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बी ए टी ए के अंतर्गत एल पी डी के अर्जन की स्थिति में एल पी डी के के संपूर्ण आई पी आर को बी ए टी ए के अंतर्गत एम एस डी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों के भाग में शामिल कर लिया जाएगा।

ख) कोरिया, इंडोनेशिया तथा चीन को शामिल करते हुए 3 क्षेत्राधिकारों में अर्जन के समस्त तीन चरण पूर्ण होने के बाद अंतिम नए लोगो तथा ब्रांड नाम का निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में "एम एस डी" का नाम बदलकर दूसरा नाम रखने की योजना है और इसलिए प्रबंधन में दोहरे कारपोरेट लोगो परिवर्तन कार्य तथा लागत से बचने हेतु कुछ समय के लिए पुरानी कं. के संकेतों (अर्थात् "एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज") को अस्थायी रूप से छोड़ने का मन बनाया है। जब नए नाम का फैसला हो जाएगा तो आशा है कि "एम एस डी" में कोई अंतिम परिवर्तन किए बिना "एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज" के सभी संकेतों के स्थान पर सीधे नया नाम रख दिया जाएगा। इस बीच पुरानी कंपनी के साथ पुराने संबंध विधिसम्मत ढंग से बनाए रखने के प्रबंधन के प्रयासों के माग के रूप में आने वाले कुछ कम लागत और/अथवा कानूनन जरूरी अथवा वांछनीय मर्दों (अर्थात् कार्यालय आपूर्तियां, लेखन सामग्री, नाम कार्ड, ई मेल पते, कंपनी वेबसाइट, आपूर्तिकर्ता/ग्राहक बीजक, नौवहन दस्तावेज, बैंक खाता, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड आदि) "एम एस डी" से बदली जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय सीमाशुल्क एम एस डी को पहले से ही एक नई कंपनी मान रहा है और उसने एन एस आर की शुरुआत से पूर्व एम एस डी द्वारा भारत को किए गए निर्यातों के लिए कोरिया हेतु "अन्य" संदर्भ कीमत लागू की है। "एम एस डी" का नाम बदलकर नया नाम रखने का प्रमुख विधिक कारण यह है कि "एम एस डी" के व्यापार नाम को वैश्विक रूप से अमरीका की एक अन्य असंबद्ध कंपनी द्वारा पूर्व पंजीकृत करा लिया गया था और इसलिए "एम एस डी" के लिए यह आवश्यक बन गया है कि आगे चलकर दीर्घावधिक और वैश्विक आधार पर "एम एस डी" के उपयोग से बचा जाए। इसके अलावा, एम एस डी के प्रबंधन को सुचारु एम एंड ए परिवर्तन प्रक्रिया तथा पुरानी कंपनी के नाम के प्रति कर्मचारियों/श्रमिक यूनियन के भावनात्मक लगाव पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एल पी डी के से एम एस डी को स्थानांतरित अधिकांश कर्मचारियों ने बी ए टी ए पूर्ण होने से पूर्व "एल जी" को समूचा कैरियर समर्पित किया था (और इसके लिए पुरानी कंपनी के संकेतों को अंततः समाप्त किए जाने तक कुछ समय की जरूरत है।)

ग) इस प्रकार आने वाले समय में "एम एस डी" का नाम बदलकर दूसरा नाम रखने की योजना है और इसलिए प्रबंधन में दोहरे कारपोरेट लोगो परिवर्तन कार्य तथा लागत से बचने हेतु कुछ समय के लिए पुरानी कं. के संकेतों (अर्थात् "एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज") को अस्थायी रूप से छोड़ने का मन बनाया है। जब नए नाम का फैसला हो जाएगा तो आशा है कि "एम एस डी" में कोई अंतिम परिवर्तन किए बिना "एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज" के सभी संकेतों के स्थान पर सीधे नया नाम रख दिया जाएगा। इस बीच पुरानी कंपनी के साथ पुराने संबंध विधिसम्मत ढंग से बनाए

रखने के प्रबंधन के प्रयासों के भाग के रूप में आने वाले कुछ कम लागत और/अथवा कानूनन जरूरी अथवा वांछनीय मदों (अर्थात् कार्यालय आपूर्तियां, लेखन सामग्री, नाम कार्ड, ई मेल पते, कंपनी वेबसाइट, आपूर्तिकर्ता/ग्राहक बीजक, नौवहन दस्तावेज, बैंक खाता, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड आदि) "एम एस डी" से बदली जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय सीमाशुल्क एम एस डी को पहले से ही एक नई कंपनी मान रहा है और उसने एन एस आर की शुरुआत से पूर्व एम एस डी द्वारा भारत को किए गए निर्यातों के लिए कोरिया हेतु "अन्य" संदर्भ कीमत लागू की है।

62. कंपनी ने यह बताया था कि वह पूर्ववर्ती कंपनी के उन्हीं ग्राहकों की जरूरत को पूरा कर रही है और निदेशक मंडल में एक नए निदेशक रखने के रूप में हुए परिवर्तन को दोड़कर कंपनी के सभी कार्यकलापों में कर्मचारी वहीं हैं।

63. जांच अवधि के बाद कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों और उनकी उत्पादन लागत के ब्यौरों का सत्यापन भी किया गया था।

64. प्राधिकारी ने कंपनियों अर्थात् एल जी ग्रुप, एल जी इंटरनेशनल एवं मेरिडियन सोलर एंड डिस्ट्रे की स्थिति का भी निम्नानुसार विश्लेषण किया:

क) इन कंपनियों के बीच संबंध के बारे में यह नोट किया गया था कि एल जी ग्रुप की नियंत्रक कंपनी एल जी कॉरप है जिसका मुख्यालय सिओल, कोरिया में है। एल जी कॉरप वर्ष 1970 से कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है और इसके 48% शेयर एल जी ग्रुप के संस्थापक श्री कू और उनके संबद्ध पक्षकारों के पास तथा शेष 52% शेयर जनता के पास हैं।

ख) एल जी कारपोरेशन की एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स, एल जी कैमिकल्स, एल जी टेलीकॉम तथा अन्य सहित 20 से अधिक सहायक कंपनियां हैं। एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व में एक विख्यात इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया सहित 75 से अधिक विनिर्माण तथा बिक्री प्रचीन हैं। एल जी ग्रुप एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसका एल जी में 33% स्वामित्व है।

ग) एल आई जी (एल जी इंटरनेशनल) एक ऐसी व्यापार कंपनी है जिसका 100% स्वामित्व जनता के पास है, मुख्यालय सिओल में तथा आई पी ओ 1976 का है। आई जी आई के विश्व भर में सूत की इंटरनेशनल, सिंगापुर सहित 75 से अधिक बिक्री प्रचालन हैं। एल जी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य एल जी ग्रुप के उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात करना है, इसलिए एल जी ग्रुप को कंपनी के नाम में एल जी ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति है। अतः एल जी आई न तो अब और न ही मूल जांच अवधि में शेयरधारिता में शेयरधारिता आदि द्वारा एल जी ई अथवा पूर्ववर्ती एल पी डी सहित एल जी ग्रुप से संबंधित नहीं है।

घ) वर्ष 2001 में एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीदरलैंड में एल जी फिलिप्स डिस्ट्रे नामक 50% तथा 50% संयुक्त कंपनी की स्थापना की और एल जी फिलिप्स डिस्ट्रे की कई सी आर टी सहायक कंपनियों की शुरुआत की।

ड) फरवरी, 2006 में सी आर टी व्यापार में गिरावट आने के कारण एल जी इलैक्ट्रॉनिक्स तथा फिलिप्स इलैक्ट्रॉनिक्स ने अपना स्वामित्व एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज को दे दिया और एल टी फिलिप्स डिस्प्लेज को नीदरलैंड न्यायालय ने अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर एल पी डिस्प्लेज कर दिया। एल पी डिस्प्लेज की कोरिया (एल पी डी-के) इंडोनेशिया, चीन बीजिंग तथा ब्राजील में कुछ सहायक कंपनियां हैं।

च) जुलाई, 2009 में एल पी डी-के सी आर टी का व्यापार और परिसंपत्तियां एक नई कंपनी तथा एम जी ए होल्डिंग कार्पो. लि. की 100% स्वामित्व वाली कंपनी मेरिडियन सोलर डिस्प्ले ने खरीद ली जिस पर श्री क्रिस पार्क का नियंत्रण है। मेरिडियन सोलर डिस्प्ले तथा एम जी ए होल्डिंग कार्पो. ने इससे पूर्व सी आर टी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री नहीं की। जांच अवधि (जुलाई, 2009 तथा दिसंबर, 2009) के दौरान मेरिडियन सोलर डिस्प्ले के केवल कोरिया सी आर टी प्रचालन थे। इस प्रकार एल जी आई न तो अब और न ही मूल जांच अवधि में एम एस डी से संबंधित है।

प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां

65. प्रकटन विवरण के उत्तर में आवेदक मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं.लि. ("एम एस डी"), कोरिया और उसके समर्थक व्यापारी एल जी इंटरनेशनल (सिंगापुर) पी टी ई लि. ("एल जी आई") सिंगापुर ने यह दलील दी है कि वे पात्र न्यू शिपर हैं और परिणामतः उनके लिए अलग-अलग नया पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए। यह भी दलील दी गई है कि यद्यपि भारतीय सीमा शुल्क ने एल पी डी कोरिया के लेबल वाले उत्पादों का निरीक्षण किया है तथापि, उन्होंने एल पी डी कोरिया (पाटनरोधी शुल्क) की दरें प्रदान नहीं की हैं। अतः न्यू शिपर के अलग निर्धारण से इंकार किए जाने से एल पी डी कोरिया को "दोहरा नुकसान" हुआ है क्योंकि एल पी डी-कोरिया के लिए भारतीय सीमाशुल्क ने एल पी डी कोरिया की दर प्रदान करने से इंकार ही नहीं किया अपितु अलग-अलग निर्धारण से भी इंकार किया और एन एस आर जांच अवधि में सत्यापन कम लागत का लाभ देने से भी इंकार किया। अतः एम एस डी ने अपने सत्यापित पाटन मार्जिन के अलग-अलग निर्धारण हेतु अपने अनुरोध को दोहराया है।

66. एल जी आई ने अपने प्रकटन पश्चात विवरण के अनुरोधों में यह उल्लेख किया है कि न तो प्रकटन की जांच और न ही दौरे की रिपोर्ट में उसके अनुरोधों से इंकार किया गया है और न ही आई जी आई द्वारा सूचित सत्यापित आंकड़ों से इंकार किया है और इस प्रकार एल जी आई को तदनुसार दर प्रदान नहीं की जा सकती।

67. घरेलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें नई उत्पादन सुविधाएं शुरू की गई हो। जिस कंपनी ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था उसने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण रूप से हस्तांतरण नए प्रबंधन को कर दिया था और नया प्रबंधन अब वही पुराना व्यापार कर रहा है। न्यू शिपर समीक्षा का उद्देश्य किसी व्यापार कंपनी के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण इस कारण से करना होता है कि (क) उक्त कंपनी द्वारा मूल मामलों की जांच अवधि में भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया था और इसलिए वह अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने के योग्य नहीं है (ख) कंपनी को मूल जांच अवधि के समय अस्तित्व में नहीं होना चाहिए और इसलिए वह अलग पाटन मार्जिन पाने की पात्र नहीं थी। तथापि, इस मामले में प्राधिकारी ने उस पूर्ववर्ती कंपनी के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित किया था जिसने उसी संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया और भारत को उसका निर्यात किया। यह स्पष्टतः ऐसा मामला है जिसमें कंपनी की नैगमिक संरचना में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, स्वामित्व में परिवर्तन होने से कंपनी का नाम भी बदल गया। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक को न्यू शिपर मानना उचित नहीं होगा। तथापि, कंपनी उन सभी लाभों के लिए स्पष्ट तौर पर पात्र है जो उसकी पूर्ववर्ती कंपनी को उपलब्ध थे। आवेदक पाटन मार्जिन के उसी स्तर और परिणामी बेंच मार्क की पूर्णतः पात्र है जो पूर्ववर्ती कंपनी को दिए गए थे।

69. प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है। इसके बजाय आवेदक को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान हेतु वही पाटन मार्जिन और परिणामस्वरूप बेंचमार्क प्रदान करना अपेक्षित है जो एल जी को दिए गए थे।

70. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के सभी अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के यप में प्रस्तुत अपने अनुरोधों में उन्होंने अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए और एल पी डी कोरिया के लिए अलग पाटन मार्जिन की मनाही से उन्हें हुए दोहरे नुकसान का मात्र उल्लेख किया है। तथापि, उन्होंने एल पी डी कोरिया के लिए पूर्व में संसतुत उन्हीं दरों पर उसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए आवेदक कंपनी पर विचार करने हेतु प्राधिकारी के प्रस्ताव के प्रतिकूल कोई पुष्टिकृत तर्क नहीं दिया है। इसके अलावा, जहां तक भारतीय सीमाशुल्क द्वारा प्रदत्त व्यवहार का संबंध है, प्राधिकारी ने यह पाया है कि जब तक शुल्क तालिका में कंपनी के नाम का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा तब तक कंपनी पर "अन्य" श्रेणी में विचार करना होगा। तथापि, केवल इस वजह से कि कंपनी को विगत में "अन्य" श्रेणी में रखा गया था, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कंपनी न्यू शिपर समीक्षा की पात्र बन गई है।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

71. प्रकटन विवरण पर याचिकाकर्ताओं के अनुरोधों सहित मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

क. जाच से इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें नई उत्पादन सुविधाएं शुरू हुई हों। जिस कंपनी ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था उसने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण हस्तांतरण नए प्रबंधन को कर दिया था और नए प्रबंधन द्वारा अब वही पुराना व्यापार किया जा रहा है, निदेशक मंडल भी लगभग वही है, वही उत्पादन सुविधाएं हैं, उसी संयंत्र और मशीनों का उपयोग हो रहा है, उसी उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है, वही कर्मचारी हैं, समान उत्पाद लोगो का उपयोग हो रहा है, उन्हीं ग्राहकों को वैसी ही विपणन का पूर्ति की पद्धति है।

ख. न्यू शिपर समीक्षा का उद्देश्य किसी व्यापार कंपनी के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण इस कारण से करना होता है कि उक्त कंपनी द्वारा मूल मामलों की जांच अवधि में भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया था और इसलिए वह अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने के योग्य नहीं है कंपनी को मूल जांच अवधि के समय अस्तित्व में नहीं होना चाहिए और इसलिए वह अलग पाटन मार्जिन पाने की पात्र नहीं थी। तथापि, इस मामले में प्राधिकारी ने उस पूर्ववर्ती कंपनी के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित किया था जिसने उसी संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया और भारत को उसका निर्यात किया। यह स्पष्टतः ऐसा मामला है जिसमें कंपनी की नैगमिक संरचना में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, स्वामित्व में परिवर्तन होने से कंपनी का नाम भी बदल गया। अतः आवेदक को न्यू शिपर मानना उचित नहीं होगा। तथापि, कंपनी उन सभी लाभों के लिए स्पष्ट तौर पर पात्र है जो उसकी पूर्ववर्ती कंपनी को उपलब्ध थे। आवेदक पाटन मार्जिन के उसी स्तर और परिणामी बैंच मार्क की पूर्णतः पात्र है जो पूर्ववर्ती कंपनी को दिए गए थे।

72. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन का नए सिरे से निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है। इसके बजाय आवेदक को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान हेतु वही पाटन मार्जिन और परिणामस्वरूप बैंचमार्क प्रदान करना अपेक्षित है जो एल पी डी - कोरिया को दिए गए थे। एल पी डी-के कोरिया में एक पृथक असंबद्ध विधिक कंपनी बनी हुई है परंतु वह जाहिर तौर पर विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं कर रही है।

73. तदनुसार प्राधिकारी दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के शुद्धिपत्र सं. 14/8/2007-डी जी ए डी की शुल्क तालिका में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश करते हैं:

i) कालम 6 में, क्रम सं. 6 के सामने उत्पादक के नाम में संशोधन किया जाए जिसे मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि. पढ़ा जाए।

ii) कालम 7 में, क्रम सं. 6 के सामने निर्यातक के नाम में संशोधन किया जाए जिसे मै. मेरिडियन सोलर एंड डिस्प्ले कं. लि. अथवा/और मै. एल जी इंटरनेशनल (सिंगापुर) पी टी ई लि., सिंगापुर पढ़ा जाएगा।

74. केन्द्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2010

Final Findings**Subject : New Shipper Review (under Rule 22) of Anti-Dumping duty imposed on imports of Cathode ray Colour Picture Tubes from Korea RP.**

No. 15/10/2009-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, (hereinafter referred as Rules) 1995 thereof;

Procedure

2. The procedure described below has been followed:

- I. M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (MSD) from Korea RP filed an application for a New Shipper Review under Rule 22 and requested the Designated Authority to initiate a 'new Shipper' review of the anti dumping duty levied on 15th May 2009 on imports of certain cathode ray colour picture tubes (CPT) originating in or exported from Malaysia, Thailand, China PR and Korea RP pursuant to the final findings dated 17th February 2009 read with the corrigendum dated 17th April 2009 in the anti dumping investigation no. 14/8/2007-DGAD.
- II. The applicants claimed that they are not related to any of the exporters/producers in Korea RP presently subject to anti dumping measures in force with regard to the aforesaid product concerned. Furthermore, they claimed that they have not exported the product concerned during the period of investigation of original investigation. They began to export after the said POI and after receiving transfer of CPT business and related assets of LPD Korea. The Authority, after prima facie examination of the information submitted by the applicants and based on the documents submitted considered it sufficient to justify the initiation of a new shipper review investigation in accordance with the provisions of Rule 22 of Anti Dumping Rules.
- III. The Designated Authority initiated the New Shipper Review on the basis of request made by M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter) from Korea RP under Rule 22 vide notification No.15/10/2009-DGAD dated 13th November 2009. The Authority recommended provisional assessment of all exports of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes by M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter) from Korea RP till the completion of the review initiated in accordance to the

Rule 22 of Indian Anti Dumping Rules. The same was notified vide Customs Notification No.144/2009-Customs on 23rd Dec 2009.

- IV. The Authority sent a copy of exporter questionnaire to M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter from Korea RP) to elicit relevant information.
- V. The period of investigation in this new shipper review is from 1st July, 2009 to 31st December, 2009.
- VI. The Authority intimated the Exporting Country about the initiation of the new shipper review investigation and gave an opportunity to all the interested parties concerned to make their view known in writing within 40 days from the expiry of the POI i.e. 1st July 09 – 31st December 2009.
- VII. The Authority provided an opportunity to all the interested parties to present their views orally in the public hearing held on 15th February, 2010. All parties who attended the hearing and presented the views orally were requested to file written submissions. The parties were also advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties in their submissions and offer rejoinders, if any. The submissions, so made, have been taken into account in the Disclosure statement.
- VIII. The Authority made available the public file as per Rule 6(7) of the Rules containing non-confidential version of the information/ submissions made by various interested parties.
- IX. **** in the findings represent information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

Product under Consideration & Like Article

3. The product under consideration in the original investigation is “complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes”, more elaborately described as “thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes such as vacuum or vapor or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, also called cathode ray tubes, television camera tubes or cathode ray colour television picture tubes, or colour television picture tubes, or colour picture tubes etc.” and has been referred to as colour picture tubes or “CPT” or “CRT” in this notification. Video and computer monitor cathode ray tubes are beyond the scope of the present petition.

4. The subject goods fall under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 under subheading no. 8540.11. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

5. The product under consideration in this investigation is “complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes”, as determined in the original case. There is no argument made by any of the interested parties on the product under consideration and like article. It is noted that the applicants have claimed that goods produced and exported by M/s. Meridian Solar

& Display Company Ltd (Producer / Exporter from Korea RP) and also exported by LG International (S'Pore) Pte.Limited, Singapore (Exporter) within the meaning of the Rules. In view of the foregoing, the Authority holds that product under consideration in the present investigations is the same as considered in the original investigation i.e., "complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes" classifiable under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975.

Views expressed by interested parties.

View of the Applicants i.e M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter from Korea RP): -

6. MSD was established on 10th April 2009 as a wholly owned subsidiary of MGA Holding Corp. Ltd organized and existing under the laws of Korea. The certificate of corporation with Business license no. 110111-4075936 was issued on 20th May 2009. In 2009, the Articles of Association of Meridian Solar & Display came into effect and became a document with binding effect regulating the organization and conduct of company and relationships between the company and shareholders and among shareholders. So far as MSD / Promoter are concerned, there are no affiliates and MSD is not related to any exporters or producers who are subject to anti-dumping duties on CPT in Korea.

7. MSD had never exported CPT to India during the POI of the original Investigations. MSD began to export CPT to India after the said POI in fact after receiving transfer of CPT business and related assets of LPD-Korea in July, 2009.

8. LPD-Korea continues to survive as distinct legal entity but no longer in the CPT Business. Thus, MSD is a new shipper.

9. MSD had proposed that the NSR Investigation Period be from 24th July 2009 to 31st January 2010 or as may be decided by the Hon'ble Authority. The Hon'ble Authority chose the POI for this NSR from 1st July 2009 to 31st December 2010. In any case MSD never claimed DM re-determination on the basis of any exports prior to 24th July 2009. MSD has no objection to the Hon'ble Authority not considering the period 1st -23rd July 2009 in the NSR POI.

10. Neither on the date of NSR request nor on the date of NSR Initiation had there been any export to India by MSD through any trader. Thus there was no suppression by MSD. But since the original Investigations included CPT originating in any of the Subject Countries, by way of abundant caution only, and to avoid any allegation of suppression or non-cooperation by an unrelated trader the single unaffiliated trader India export at the end of the NSR POI was reported by MSD and the unaffiliated trader (namely LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore) was requested to file a supporting trader Response which it did. All other India exports were directly by MSD. Thus, MSD can receive NSR DM re-determination based on its own response. In any case all exports by MSD were at the others rate till NSR initiation and on bond thereafter.

11. MSD does not share any shareholder or Director with LPD-K, LPD, LG, LGE, LGI etc or with the Court appointed Administrators of LPD. MSD is also not owned or controlled by any

third company that owns or controls LPD-K, LPD, LG, LGE, LGI. Obviously for marketing MSD as a new entrant to the business will rely on the established experience of its acquired assets in producing quality CPT.

12. The COO is not on MSD's Board of Directors and was neither COO nor comparable seniority in LPD-K/LPD. It is not common for all executives below Director Level to be changed whenever there is such a sale. That only 1 executive has continued at that level reflects the overall complete change of 'control'.

13. The Domestic Industry has challenged the Authority's decision to initiate the New Shipper Review. The grounds of their grievances are simply inaccurate and ill-conceived. The applicant producer exporter is a legal entity created by law and not a natural person. A company created by law comes into existence only when it gets its registration or in other words when it is incorporated. The certificate of incorporation or registration shows the conclusive evidence as regards the date when a legal entity like MSD comes into existence. We have submitted a copy of registration certificate to the Authority evidencing that the company came into being only in 2009. Hence it is confirmed that during the period of investigation of the original investigation it did neither exist nor did export the subject goods to India. Being a new entrant to the product, it is surely a new exporter and eligible for a separate dumping margin to be determined by a New Shipper review as provided by the India Anti-Dumping Law. LPD-K continues as a separate unrelated legal entity in Korea.

14. From the submissions by the consultants for the Domestic Industry, it appears that they are confused about change of name and coming into existence of a new entity. In case of a change of name, the entity continues with the same with old registration number and date but gets an approval from the registering Authority for change of name with effect from the date of such approval. No new certificate of registration is issued. It was made amply clear before the Authority that our company is a new one registered with the concerned Authority. It is nowhere stipulated that a new company is required to establish a new production facility of its own. It is well authorized by modern governments in almost all countries that a new company or entity can acquire an existing plant and start production therein instantly. In India also many Indian production facilities are being acquired by new entities. Acquiring the production facility of an existing unit does not mean that the new company existed or produced the concerned goods before its date of incorporation. Our company was incorporated only in 2009 and hence the question of production or exports in the original investigation does not arise.

15. The Domestic Industry seems to be confused over the term 'Producer'. Being themselves confused, they have tried to confuse the Authority by equating 'producer' with 'production facilities'. Producer is one who produces irrespective of the ownership of the production facilities. A producer may not own a production facility but get its production in other's factory on 'job work' basis or on rental. So ownership is no issue so far as 'production' or 'producer' is concerned. Producer is one, either a natural person or a legal entity, who produces irrespective of ownership of the production facility. It's not obligatory for a producer to own a plant/factory. MSD has purchased an existing unit and got the subject goods produced after its incorporation. So MSD has become a producer of the Subject Goods only after 22nd July, 2009 and not earlier. Hence there is no doubt about its status as a new producer.

16. The following extracts from the written submissions of the Domestic Industry also substantiate their confusion,

“The followings collectively form a producer –

- a) Ownership – in as much as they bring the capital and own the assets & assume the liabilities;
- b) Management – a company is managed by a number of persons who are known as management;
- c) Manpower – a company is run by a number of manpower, which includes skilled, semi-skilled and unskilled manpower;
- d) Machines – a company produces the article using machines, especially deployed and used to produce the product;
- e) Materials – a company uses laid down materials in order to produce the product;
- f) Money – a company requires money to run its operations.

Domestic industry submits that when all of the above is put together, an entity gets formed who produces and sells the goods in the market.

17. In the context of dumping margin and anti dumping duty, the relevance of the above is explained below:-

■ The management of the company is responsible for day to day production and sale of the product under consideration. It is this management who decides the volume and the price that should be sold in a particular market. It is the management of the company who takes a decision on where to sell the product, at what prices and what volumes. While it is true that the management takes directions or orders from the Board, it may be recognized and appreciated that day to day sale of the product and the price is generally governed by the management.

■ The normal value is intrinsically linked to cost of production. Such cost of production is a sum of costs on account of materials, labor cost, processing/manufacturing cost, depreciation, and other costs.”

18. From above the Domestic Industry feels that when all of ownership, management, manpower, machines, materials and money are put together, an entity gets formed who produces and sells the goods in the market. They are confused again. Ownership does not mean the producer needs to be the owner of the production facilities. Along with the production facilities of others a producer can use the manpower of the latter. If DSM Anti-infective produces 6APA in the factory of Alka Remedies on job charges basis DSM Anti-infective remains the producer.

19. While analyzing the relevance of the above factors in the context of anti-dumping duty they are again confused. Not the ownership but the management is more important. Neither production facility nor the ownership influences the cost of production, selling price, sales volume. It is the efficient management that converts a loss making company to a profit making one. The cost, price and profitability of IPCL changed when the management has gone to RIL. The same manufacturing facility gives different results with the change of management from an inefficient to an efficient one. The domestic industry assumes that cost of production, normal

value, export price everything will continue to be the same as the production facility of our company has been taken over from an existing company. The management makes all the changes as has been done to IPCL when it has been taken over by RIL. MSD has its own management and own vision and cost and marketing strategy. MSD has its own production, own cost and own marketing policy. MSD is open to the Authority to verify its cost, domestic selling prices, export prices. If the Hon'ble Authority finds any dumping it will determine separate dumping margin and recommend AD duty accordingly. The Authority is right in considering MSD as a new producer and initiating the investigation as per Rules after careful consideration of the Request and documents filed. The objection of the Domestic Industry is based on misconception only.

20. MSD is committed to co operate the Authority in the investigation with all relevant information. Moreover, the Domestic Industry has not led any evidence to indicate that the shareholders of LPD-K and MSD are common or that there are any common Directors on the respective Boards of Directors or that MSD and LPD-K are owned by a common company. There is no such common shareholding, Director or common control or any affiliation.

21. It is ownership and management that is responsible for dumping and not plant or machinery. Otherwise there would be no provision for individual dumping margin determination and various Authorities, including DGAD, would not have found different dumping margins for different companies having similar plant and machinery even, at times, from the same country in so many investigations across jurisdictions. Hence, the Domestic Industry's submissions are contrary to the very basis and logic of anti-dumping investigations.

22. The facts of the FDY MTR concerning Malaysia are *prima facie* different since it is nowhere recorded in the Findings that there were no common Directors between Hualon and Recron or that Hualon Malaysia legal entity survived the acquisition (though without its assets), and also since the new owners, Reliance Group, were admittedly in existence during the POI of the concerned original investigations and were admittedly producers of the Subject Goods in the POI of the concerned original investigations. The facts on record in respect of MSD are completely different.

23. MSD as a producer exporter can gain individual determination in this NSR either on its own or also together with LGI. MSD does not oppose POI commencing 22 July 2009. MSD **requests** the Hon'ble Authority to also keep in mind the doctrine of 'Balance of Convenience'. The alternative would not be convenient to the Hon'ble Authority, *i.e.*, immediately initiating a MTR on the basis of MSD's request for NSR (treating the same as MTR Request).

24. Moreover, the Hon'ble Authority will be mindful of its well established practices and Indian provisions. The Domestic Industry did not in the NCV WS enclose the relevant extracts from or citation of the evidence of EU/EC practice that they relied on though these would be published material and thereby could not be deemed to be confidential by any stretch of the concept. MSD reserves the right to comment further on this once the details are disclosed. As can be seen from the FDY MTR case above relied on by the Domestic Industry the relevant facts of each case must be carefully assessed on their own.

LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore (Trader/Exporter).

25. LGI is not related to MSD, LGE, LPD, LPD Korea or the Netherlands Court appointed Administrators of LPD. The shareholders and Directors are different and LGI is not owned or controlled by any common company.

26. LGI is not related to any exporters or producers who are subject to anti-dumping duties on CPT in Korea.

27. Neither on the date of NSR Request nor on the date of NSR Initiation had there been any export to India of the concerned CPT by LGI. Thus there was no suppression by LGI. But since the original Investigations included CPT originating in any of the Subject Countries, by way of abundant caution only, and to avoid any allegation of suppression or non-cooperation by an unrelated trader LGI agreed to MSD's request to file a supporting trader Response. Thus, LGI can receive NSR DM determination based on its own response for MSD products. The Domestic Industry conceded at the Hearing that a single transaction is sufficient.

28. The Hon'ble Authority is bound by Rule 22 and the ADA. The Rules emphasize 'control' for which ownership is a test. LGI does not share any shareholder or Director with MSD, LPD-K, LPD, LG, etc or with the Court appointed Administrators of LPD. LGI is also not owned or controlled by any third company that owns or controls MSD, LPD-K, LPD, LGE. LGI is not related now or in the POI to MSD, LGE, LPD-K etc. Moreover, the Domestic Industry has not led any evidence to indicate that the shareholders of LGE, LPD-K and LGI are common or that there are any common Directors on the respective Boards of Directors or that LGI and LPD-K are owned by a common company. There is no such common shareholding, Director or common control or any affiliation.

29. LGI would not be eligible for a Corrigendum hence a Review is appropriate. LGI must be eligible for some remedy. Since LGI does not believe it's a related party it believes it is eligible to participate in this NSR.

30. Original LPD Holding Company was a CPT specific joint venture owned 50:50 by certain LG and Philips group companies that were themselves special vehicles within the respective groups in order to avoid LG and Philips groups being treated as a combination for all products under the similar relationships provisions in most jurisdictions in company law and competition law.

31. It is not a case where a LG group company would own 50% and the balance dispersed. Here a Philips group company owned the entire balance 50%. So on the basis of shareholding on this case neither LG nor Philips groups could be said to control the LPD Group. Further, in any case from early 2006 the Netherlands court appointed independent Administrators to control the management of LPD. Hence, neither LG nor Philips Groups were in law in any manner involved in the management of LPD group companies in the POI in the original investigations or thereafter. LGI also does not object to the NSR POI commencing from 22 or 24 July 2009 instead of 1st July 2009. For all these reasons LGI believes it is an eligible new shipper and entitled to participate in the instant NSR and seek individual DM determination.

32. The domestic industry conceded that even one transaction is sufficient so LGI would be entitled to Review. In case of MTR the Hon'ble Authority would be constrained to for the same transaction again open a file, initiate MTR, devote resources, and conduct the same verification in Korea and Singapore and so on. Thus from the 'balance of convenience' point of view too LGI may be permitted to participate in the said NSR.

33. In case, Hon'ble Authority takes a different view, LGI's Response may be treated as an Application for MTR as over a year has passed since provisional duties and the Hon'ble Authority may initiate a MTR.

34. It is ownership and management that is responsible for dumping and not plant or machinery. Otherwise there would be no provision for individual dumping margin determination and various Authorities, including DGAD, would not have found different dumping margins for different companies having similar plant and machinery even, at times, from the same country in so many investigations across jurisdictions. Hence, the Domestic Industry's submissions are contrary to the very basis and logic of anti-dumping investigations.

35. The facts of the FDY MTR concerning Malaysia are *prima facie* different since it is nowhere recorded in the Findings that there were no common Directors between Hualon and Recron or that Hualon Malaysia legal entity survived the acquisition (though without its assets), and also since the new owners, Reliance Group, were admittedly in existence during the POI of the concerned original investigations and were admittedly producers of the Subject Goods in the POI of the concerned original investigations. The facts on record in respect of LGI are completely different.

36. LGI as a supporting trader can gain individual determination in this NSR together with MSD. The Hon'ble Authority may also keep in mind the 'Balance of Convenience' both to itself as well as to LGI and MSD. LGI also does not oppose POI commencing 22nd July 2009. Alternately, the Hon'ble Authority may treat LGI's supporting response as a request for MTR.

37. Moreover, the Hon'ble Authority will be mindful of its well established practices and Indian provisions. The Domestic Industry did not in the NCV WS enclose the relevant extracts from or citation of the evidence of EU/EC practice that they relied on though these would be published material and thereby could not be deemed to be confidential by any stretch of the concept. LGI reserves the right to comment further on this once the details are disclosed. As can be seen from the FDY MTR case above relied on by the Domestic Industry the relevant facts of each case must be carefully assessed on their own.

Views of Samtel Colour Limited, a constituent of the domestic industry

38. The circumstances stated in the present case are insufficient to consider the present case under Rule 22.

39. The management of the company is responsible for day to day production and sale of the product under consideration.

40. The normal value is intrinsically linked to cost of production. Such cost of production is a sum-of costs on account of materials, labor cost, processing/manufacturing cost, depreciation, and other costs.

41. In the instant case, admittedly, it is only the ownership that has changed after the last investigation period. It is not even the case of the petitioner that with the change in the ownership, management, manpower, machines and materials have undergone a change. The applicant has not even claimed that any factor responsible for normal value has changed as a result of ownership.

42. The general practice with respect to name change is that the request for change in name can only be accepted if the change in name in no way affects the findings of the regulation imposing the anti dumping duty.

43. It is for the applicant to demonstrate whether the facts pertaining to their case relate to mere change of name or the change in the ownership is so fundamental with regard to parameters relating to normal value that the dumping margin is fundamentally different than the dumping margin determined earlier.

44. Since prima facie full ownership along with manpower, machines, market and material all the assets are transferred from the M/s LG Phillips Displays Korea Co. Ltd. to M/s Meridian Solar Display Company Ltd. then there exists no circumstances which justify consideration of the applicant as a new producer. Mere change in the ownership of the company does not mean that the structure and identity of the company has so fundamentally changed that the applicant can be considered as new producer. All the assets and liabilities of the old company have been transferred to the new company. The applicant does not satisfy the legal requirements under Rule 22 to bring an application before the Authority. The evidence with respect to the structure of M/s Meridian Solar Display Company Ltd. and its relation with the M/s LG Phillips Displays Korea Co. Ltd. is already made available to the Authority at the time of hearing.

45. The Designated Authority is conducting other investigations for situations arising out of almost similar circumstances in the matter of "All fully Drawn or Fully Oriented Yarn/spin Drawn Yarn/Flat Yarn originating in or exported from Indonesia, Korea RP, Malaysia and Chinese Taipei".

46. Undisputedly, the Plant was under the control of Bankruptcy Trust at the time of original investigations. LPD made certain claims with regard to its legal status and ownership at the time of original investigations. Ownership/control undisputedly continued with the same entity that had ownership/control during the period 1-23rd July 2009. There are admittedly exports during the period. Such being the case, it cannot be established that there were no exports from the same plant during the original investigation period and current investigation period.

47. Investigation period in the present case is from 1st July, 2009. Admittedly, the present company was incorporated w.e.f 22nd July, 2009. Between 1st to 21st July, 2009, the company was being owned and controlled by the same management as was controlling it during the period of

original investigations. Thus, admittedly, the applicant cannot claim that it has not exported during the period of original investigations.

48. Two sales channels have been used by the applicant producer – (a) direct, and (b) through LG International. LG International is clearly related to the producer who was investigated by the Designated Authority.

49. At the time of original investigations, the producer was LG Phillips, a company which was owned by LG, Korea and Phillips.

50. In the current period, exports to India have been made by LG International. Undisputedly, LG International is related to the LG, Korea.

51. In view of the above, the current producer-exporter combination is related to the producer-exporter combination in the original investigations. On this account as well, the conditions relating to new shipper review are not satisfied.

52. Rule 22 refers to both producer and exporter. The said Rule does not restrict at producer. Further, it does not refer to “related exporter” of the producer. Therefore, it is entirely immaterial that the exporter is not related to the producer. The word producer and exporter can be seen interchangeably, when both have been specifically provided under the Rules.

53. The applicant has not established that there were no exports in the period of original investigations. Nor has the applicant established that they were not related to any of the exporter/producer during the original investigation period. Additionally, one of the exporters in the current period is clearly related to an exporter in the previous investigation period. On all these accounts, the petition for separate dumping margin under rule 22 is clearly inappropriate.

54. Barring ownership, nothing has changed between the previous investigation period and current investigation period.

55. Concluding their submissions, the Domestic Industry has stated as under:

- i. Domestic industry and applicant both are agreeable on change of name.
- ii. Change in the legal status does not mean “new company”.
- iii. New shipper review provision has been brought in to address concerns of those producers who either did not export in that period or who came into production subsequently.
- iv. Ownership alone cannot be a barometer of “producer”. Producer is a much wider term and includes ownership, management, manpower, machines, money, and materials.
- v. Barring ownership, nothing has changed. There is no factor due to which normal value or export price or dumping margin could have changed as a result of this ownership. Further, even if dumping margin changes, it is a matter of midterm review.

- vi. If dumping margin is to be reviewed, domestic industry requests imposition of specific duty.
- vii. The application of the Applicant may be rejected;
- viii. The proceedings initiated may be terminated as the application does not satisfy the legal requirements under Rule 22;
- ix. The domestic industry however does not have objection to grant of the same level of anti dumping duty to the applicant as was given to LG Phillips, the company who was investigated by the Designated Authority.

Examination by the Authority

56. The Designated Authority initiated new shipper review keeping in view the provisions of the anti dumping rules, which are reproduced below:

“Rule 22: (1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee form the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review”.

57. Rule 22 clearly specifies the circumstances under which a new shipper investigation can be carried out for the purpose of calculating individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied;

- a. That the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation and,
- b. That exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product concerned.

58. It is evident from the above that the intention of Rule 22 is to determine individual dumping margin in respect of an exporter or producer who did not export the subject goods in the period of original investigation. Since such producers/ exporters did not export subject goods in

the period of original investigation, the Designated Authority could not have determined dumping margin in respect of their exports at the time of original investigations. The purpose of the new shipper review provision is therefore to provide an opportunity to such an exporter to claim their own dumping margin considering that these exporters have been granted residual dumping margin during the original investigations.

59. In the instant case, M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter from Korea RP) made the application for new shipper review. Subsequent to the initiation and after the POI, the response was filed (apart from M/S Meridian Solar & Display Company Ltd, Korea) also by LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore (Exporter) claiming to have exported PUC manufactured by the subject producer in Korea RP.

60. In their application, the applicants made, inter-alia, the following claims: -

- a. That the applicants had not exported the material during the period of original investigation;
- b. That the applicants were not related to any exporter or producer who had exported during the period of original investigations.

61. The Authority conducted on-the-spot verification of the data furnished in the form of questionnaire by M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd (Producer / Exporter from Korea RP) and LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore (Exporter). During the physical verification of records of the producer in Korea RP, and at the time of visit to the factory premises at Gumi, it was noticed that the name displayed at the factory continued to be LG Philips Displays, that is what was there before the acquisition of the assets and liabilities by the newly set up Meridian Solar displays, the company that has sought NSR and consequent individual dumping margin. A visit to the warehouse also revealed that they continued to have the same Logo as of the erstwhile LP Displays and the CRT / CPT manufactured were also marketed in the name of LG Philips Displays as per labels affixed on the manufactured product and ready for shipment to different destinations. In its reply to the verification report issued about the rationale of retaining the LOGO etc. of the erstwhile LP Displays, following submissions were made:

a) As was clear from the BATA (Business and Assets Transfer Agreement) filed, the sale of LG. Philips Displays Korea Co., Ltd. ("LPDK") to Meridian Solar & Display Co., Ltd. ("MSD"), a wholly-owned subsidiary of MGA Holding Corp Limited, registered in Hong Kong, was stage 1 of the 3 umbrella transactions, of which stages 2 and 3 involve acquisition of Indonesia and Beijing units which process is yet to be completed as there are a number of outstanding items to be achieved to close a deal. Subsequently, there may also be a potential acquisition of part of the Brazil operations of former LPD but this isn't yet decided. In case of the acquisition of LPDK under the BATA, the full IPR of LPDK has been included as part of the transferred assets under the BATA to MSD.

b) The final new logo and brand name will be decided after the completion of the full 3 stages of acquisitions in 3 jurisdictions covering Korea, Indonesia and China. There is thus a plan to change "MSD" to another new name in coming period so the management formed a

view to temporarily leave the Old Co signs (i.e., "LG Philips Displays") for the time being to avoid repetitive corporate logo change work and costs. Once the new name has been decided in due course, it is expected that all signs of "LG.Philips Displays" will be permanently replaced with the new name directly without having to make an interim change to "MSD". In the meantime, as part of the management's efforts to legally sever the past relationship with the Old Co, certain less cost incurring and/or legally necessary or desirable items (e.g., office supplies, stationeries, name cards, email addresses, company website, supplier/customer invoices, shipping documents, bank accounts, property ownership records, etc.) had already been changed to "MSD". It may be noted that in Indian Customs are already treating MSD as a new entity and applied the 'others' reference price for Korea for exports to India by MSD prior to initiation of the NSR. The reason for another change from "MSD" to the new name is mostly due to legal reasons that the trade name "MSD" had been pre-registered globally by another unrelated company in the US and it has thus become necessary for "MSD" to avoid using "MSD" on a long term and global basis going forward. Further, the management of MSD needs to take into account for a smooth M&A transition process the employees/labor union's emotional attachment to Old Co's name as most of the transferred employees from LPDK to MSD had devoted their entire career at "LG" prior to the BATA closing (and this requires some time till the Old Co signs can be finally put away".

c) There is thus a plan to change "MSD" to another new name in coming period so the management formed a view to temporarily leave the Old Co signs (i.e., "LG.Philips Displays") for the time being to avoid repetitive corporate logo change work and costs. Once the new name has been decided in due course, it is expected that all signs of "LG.Philips Displays" will be permanently replaced with the new name directly without having to make an interim change to "MSD". In the meantime, as part of the management's efforts to legally sever the past relationship with the Old Co, certain less cost incurring and/or legally necessary or desirable items (e.g., office supplies, stationeries, name cards, email addresses, company website, supplier/customer invoices, shipping documents, bank accounts, property ownership records, etc.) had already been changed to "MSD". It may be noted that in Indian Customs are already treating MSD as a new entity and applied the 'others' reference price for Korea for exports to India by MSD prior to initiation of the NSR.

62. It was stated by the company that they have been catering to the same profile of customers as have been taken over from the erstwhile company and except change in the Board of Directors by having one new Director, Rest of the staff in all the functions of the company being the same.

63. The details in respect of the exports made by the company after the POI and their cost of production were also verified.

64. The authority also analyzed the position of companies namely LG Group, LG International and Meridian Solar & Displays as follows:

a) Regarding the relationship among these companies, it was noted that LG Group holding company is LG Corp., which headquartered in Seoul, Korea. LG Corp. is Korean stock exchange listed company since 1970 and 48% of its shares are hold by Mr. Koo, a founder of LG Group and his related parties and other 52% by public.

b) LG Corp. has more than 20 subsidiaries including LG Electronics, LG Chemicals, LG Telecom and others. LG Electronics is a famous electronic company in the world, has more than 75 worldwide manufacturing and sales operations, including LG Electronics India. LG Corp. is a largest shareholder of LG Electronics, has 33% of LG Electronics ownership.

c) LGI (LG International) is trading company owned 100% by public, head office in Seoul and IPO in 1976. LGI has more than 75 worldwide sales operations, including LG International Singapore. LG International is mainly engaged in LG Group products export to other countries, therefore, LG Group allowed to use LG brand in the company name. Thus LGI is not related now or in POI in original investigations by shareholding etc with LG Group including LGE or former LPD

d) In 2001, LG Electronics and Philips Electronics set up 50% and 50% Joint Company, LG Philips Displays in Netherlands and spun off various CRT subsidiaries to LG Philips Displays.

e) Due to declining CRT business, In Feb 2006, LG Electronics and Philips Electronics gave up its ownership to LG Philips Displays, and LG Philips Displays was taken over by Netherland court, and changed company name to LP Displays. LP Displays, has some subsidiaries in Korea (LPD-K), Indonesia and China Beijing and Brazil.

f) In July 2009, LPD-K CRT Business and assets bought by Meridian Solar Display, new Company and 100% owned by MGA Holding Corp. Limited hold by Mr Chris Park. Meridian Solar Display and MGA Holding Corp. did not produce and sale of CRT product before. During the POI (from July 2009 and December 2009), Meridian Solar Display only has Korea CRT operations. Thus LGI is not related now or in POI in original investigations to MSD.

Comments to Disclosure Statement

65. In response to the disclosure statement, the applicant M/S Meridien Solar & Display Co., Ltd ("MSD"), Korea and its supporting trader LG International (S'pore) Pte Ltd ("LGI"), Singapore have pleaded that they are eligible new shipper and consequently a fresh individual dumping margin should be determined for them. It has also been pleaded that while Indian Customs have inspected the products with LPD-Korea labels, they have not extended LPD-Korea (anti dumping duty) rates. Hence, denial of new shipper's individual determination subjects LPD-Korea to 'double jeopardy' as MSD, Korea was denied LPD-Korea rate by Indian customs but is also denied the individual determination and is also denied the benefit of verified lower costs in the NSR POI. MSD thus reiterates its request for individual determination of its verified dumping margin.

66. LGI in its post disclosure statement submissions has stated that neither the disclosure examination nor tour report deny its submissions nor deny the verified data reported by LGI nor thus LGI may be granted its rate accordingly.

67. The Domestic Industry has reiterated their earlier submissions.

Examination by the Authority

68. The Authority holds that the investigation has established that it is not a case where new production facilities have come in operation. The company which had exported the product under consideration to India during the original investigations period had completely transferred its assets and liabilities to new management and the new management is now undertaking the very same old business. The objective of new shipper review is to determine dumping margin in respect of a business entity for the reason that (a) the entity might not have exported the product to India during the POI of original case and therefore was not able to get individual dumping margin, (b) the entity might not have even come into existence at the time of original POI and therefore was not able to get individual dumping margin. In the instant case, however, the Authority had determined dumping margin in respect of erstwhile company, which had produced the product under consideration at the same plant and exported to India. It is clearly a case where Corporate Structure of the company has undergone a change. Further, with the change in the ownership, the name of the company has also undergone a change. The Authority therefore holds that it would therefore not be appropriate to consider the applicant as a new shipper. However, the applicant is clearly entitled for all the benefits that were available to its predecessor company. The applicant is clearly entitled for the same level of dumping margin and consequent benchmark as was given to the predecessor company.

69. The Authority considers that the individual dumping margin in respect of exports made by the applicant is not required to be determined. Instead, the applicant is required to be given the same level of dumping margin and consequently the benchmark for payment of anti dumping duties as was given to LG.

70. The Authority has carefully examined the submissions made by the Petitioner. In their submissions, submitted as comments to the Disclosure statement, they have made a mere statement seeking individual DM and facing Double Jeopardy of denial of individual DM earmarked for LPD Korea to them. They however have not come up with any substantive argument contrary to the proposal of the Authority to recommend the same anti dumping duty benchmark at the same rates, as were earlier recommended for LPD Korea, to be considered for the applicant company as well. Further, as regards treatment accorded by the Indian Customs, the Authority observes that unless the name of the company is specifically brought in the duty table, the company has to be considered in "others" category. However, merely because the company was being placed in "others" category in the past, the same does not imply that the company becomes entitled to new shipper review.

Conclusion and Recommendations

71. Having considered all the aspects of the case, including submissions made by the petitioners to the Disclosure Statement, the Authority concludes that:

- a. The investigation has established that it is not a case where new production facilities have come in operation. The company which had exported the product under consideration to India during the original investigations period had completely transferred its assets and liabilities to new management and the new management is now undertaking the very same old business, almost the same composition of board of directors, having same production facilities, utilizing same plant & machineries, producing the same product, deployed the same employees, using the same product logo, same or similar marketing and catering to same customers.
- b. The objective of new shipper review is to determine dumping margin in respect of a business entity for the reason that the entity might not have exported the product to India during the POI of original case and therefore was not able to get individual dumping margin. The entity might not have even come into existence at the time of original POI and therefore was not able to get individual dumping margin. In the instant case, however, the Authority had determined dumping margin in respect of erstwhile company, which had produced the product under consideration at the same plant and exported to India. It is clearly a case where Corporate Structure of the company has undergone a change. Further, with the change in the ownership, the name of the company has also undergone a change. It would therefore not be appropriate to consider the applicant as a new shipper. However, the applicant is clearly entitled for all the benefits that were available to its predecessor company. The applicant is clearly entitled for the same level of dumping margin and consequent benchmark as was given to the predecessor company.

72. In view of the above, the Authority holds that the individual dumping margin in respect of exports made by the applicant is not required to be determined afresh. Instead, the applicant is required to be given the same level of dumping margin and consequently the benchmark for payment of anti dumping duties as was given to LPD Korea. LPD-K continues as a separate unrelated legal entity in Korea, however confirmedly, without being in the manufacture of the Product under Consideration.

73. Accordingly, the authority recommends following amendments in the Duty table in the Corrigendum No. 14/8/2007-DGAD dated 17th April 2009:

- i) Against serial no. 6, in col. 6, the name of the Producer may be amended to read as M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd.

ii) Against serial no.6, in col. No.7, the name of the exporter may be amended to read as M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd. or/ and M/s LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore.

74. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this order shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

P. K. CHAUDHARY, Designated Authority